

V.G. 14173  
16/6/04

रजिस्ट्री सं. डो० एल०-33004/99

राजत सरकार मुद्रणालय 9790  
दि० दिनांक 21-6-04  
REGD. NO. D. L.-33004/99



प्रभारी  
सरकार विभाग

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.D. 500

KM 30

Dept. 250

UP 220

सं. 173]  
No. 173]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2004/चैत्र 11, 1926  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2004/CHAITRA 11, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

सं. 4/2004-सेवा कर

पूरा किया

प्रभारी  
रा० वि० एकम

सा.का.नि. 248(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) दिनांक 21 नवम्बर, 2002 में सा.का.नि.777(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2002 के तहत जारी भारत सरकार की अधिसूचना सं. 17/2002-सेवा कर का अधिक्रमण करते हुए और ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा न की गई चीजों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, एतद्वारा विशेष आर्थिक जोन के किसी विकासक को अथवा विशेष आर्थिक जोन की किसी इकाई को (निर्माणाधीन इकाई सहित) ऐसे विशेष आर्थिक जोन के भीतर सेवाओं की उपयोगिता के लिए किसी सेवा प्रदाता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (I) के खंड (90) में यथा परिभाषित दी गई किसी प्रकार की कराधेय सेवा को कुछेक्ष शर्तों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से छूट देती है, अर्थात् :-

(i) विकासक को विशेष आर्थिक जोन का विकास, सचालन और रख-रखाव करने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है;

- (ii) विशेष आर्थिक जोन की इकाई को विशेष आर्थिक जोन में इकाई स्थापित करने के लिए विकास आयुक्त अथवा अनुमोदन बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित किया गया है;
- (iii) विशेष आर्थिक जोन का विकासक अथवा इकाई उक्त कराधीय सेवाओं की प्राप्ति और उसके प्रयोग का उपयुक्त लेखा जोखा रखेगी।

**व्याख्या:-** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-

- (1) "अनुमोदन बोर्ड" का आशय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी राजपत्र में यथा अधिसूचित निर्यातोन्मुखी इकाई और विशेष आर्थिक जोन इकाइयों के लिए संयुक्त अनुमोदन बोर्ड से है;
- (2) "विकासक" का आशय विशेष आर्थिक जोन के विकास अथवा संकार्य अथवा रख-रखाव में लगे व्यक्ति से है और इसमें ऐसे किसी विकासक द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति भी शामिल है;
- (3) "विशेष आर्थिक जोन" का आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के परंतुक की व्याख्या-2 के खंड (iii) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोन के रूप में विनिर्दिष्ट जोन से है।

[का. सं. 305/55/2003-एफ.टी.टी.]

वी. केज़ो, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2004

No. 4/2004-Service Tax

G.S.R. 248(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs ( Department of Revenue), No. 17/2002-Service Tax, dated the 21<sup>st</sup> November, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 21<sup>st</sup> November, 2002, vide, G.S.R. 777(E), dated the 21<sup>st</sup> November 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts taxable service of any description as defined in clause (90) of sub-section (1) of section 65 of the said Act provided to a developer of Special Economic Zone or a unit (including a unit under construction) of Special Economic Zone by any service provider for

consumption of the services within such Special Economic Zone, from the whole of service tax leviable thereon under section 66 of the said Act, subject to the following conditions, namely:-

- (i) the developer has been approved by the Board of Approvals to develop, operate and maintain the Special Economic Zone;
- (ii) the unit of the Special Economic Zone has been approved by the Development Commissioner or Board of Approvals, as the case may be, to establish the unit in the Special Economic Zone;
- (iii) the developer or unit of a Special Economic Zone shall maintain proper account of receipt and utilisation of the said taxable services.

*Explanation* .- For the purposes of this notification,-

- (1) “Board of Approvals” means the combined Board of Approvals for export oriented unit and Special Economic Zone units, as notified in the Official Gazette, from time to time by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry;
- (2) “developer” means a person engaged in development or operation or maintenance of Special Economic Zone, and also includes any person authorised for such purpose by any such developer;
- (3) “Special Economic Zone” means a zone specified as Special Economic Zone by the Central Government in the notification issued under clause (iii) of *Explanation 2* to the proviso to sub-section (1) of section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

[F. No. 305/55/2003-FTT]

V. KEZO, Under Secy.